श्री शरद यादवः इसलिए मेरा यह कहना है कि चुनाव में जो वायदे किए जाएं, उन्हें पूरी तरह लागू किया जाए। ...(व्यवधान)... यह बात पक्की होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार)ः महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

12.00 Noon

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तराखंड में नए विमानपत्तन

- *106. श्री तरुण विजय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) उत्तराखंड में किन-किन स्थानों पर नए विमानपत्तनों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है; और
- (ख) पंत नगर से प्रतिदिन सुबह और शाम के समय दिल्ली और मुंबई के लिए विमान सेवाएं कब तक आरंभ कर दी जाएंगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री अशोक गजपित राजू पुसापित)ः (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

- (क) नागर विमानन मंत्रालय को उत्तराखंड राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्तिगत विकासकर्ता की ओर से उत्तराखंड में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
- (ख) सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं का बेहतर विनियमन प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश (आरडीजी) निर्धारित किए हैं। एयरलाइनें मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन देश में कहीं भी प्रचालन के लिए स्वतंत्र हैं। अनुमोदित शीत अनुसूची 2015 के अनुसार, एलाइंस एयर दिल्ली-पंत नगर सेक्टर पर अपराह्न में प्रति सप्ताह 4 उड़ानों की आवृत्ति के साथ अनुसूचित घरेलू उड़ाने प्रचालित कर रही है।

New airports in Uttarakhand

†*106. SHRI TARUN VIJAY: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

- (a) the locations in Uttarakhand where the construction of new airports is proposed; and
- (b) by when Pant Nagar would be connected to Delhi and Mumbai by daily morning and evening flights?

[†]Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU PUSAPATI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

- (a) Ministry of Civil Aviation has not received any proposal from the State Government of Uttarakhand or any other individual developer for setting up of new Greenfield Airports in Uttarakhand.
- (b) Government has laid down Route Dispersal Guidelines (RDG) with a view to achieve better regulation of air transport services of different regions of the country. Airlines are free to operate anywhere in the country subject to compliance of Route Dispersal Guidelines. As per approved Winter Schedule 2015, Alliance Air is operating schedule domestic flight on Delhi-Pant Nagar sector with a frequency of 4 flights /week in the afternoon.

श्री तरुण विजयः सर, में माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि मैंने जो प्रश्न दिया था, उसमें मुझे आशा थी कि वे उत्तर में उत्तराखंड के एयरपोर्ट्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे। देश में उत्तराखंड अकेला एक ऐसा प्रांत है, जिसकी जनसंख्या एक करोड़ है और वहां दो करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्री प्रति वर्ष आते हैं। सर, वहां एयरपोर्ट्स की क्या स्थिति है? Security area में 75 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाला देहरादून एयरपोर्ट है, जिसमें maximum 275 पैसेंजर्स आ सकते हैं। 2010 में एक लाख पैसेंजर्स की क्षमता वाला एयरपोर्ट बना था, उस एयरपोर्ट पर आज प्रति वर्ष 4 लाख एयर ट्रैवलर्स आते हैं, लेकिन वहां की स्थिति क्या है? माननीय मंत्री जी, कृपया इस विषय में बताएं कि पतनगर और देहरादून एयरपोर्ट्स को कब विस्तारित किया जा सकता है? जिस प्रांत में चार करोड़ पर्यटक आते हैं, उस प्रांत में एयर कनेक्टिविटी के लिए केवल एक एयरपोर्ट है, जहां पर केवल 75 यात्री security क्षेत्र में और 275 यात्री पूरे एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। मंत्री जी, उत्तराखंड को इससे बेहतर एयरपोर्ट की सुविधा चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Question, please, not a speech.

श्री तरुण विजयः मुझे विश्वास है कि आपका ध्यान हमारी ओर है, लेकिन उत्तराखंड में इस एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU PUSAPATI: Sir, there are two airports in the State. One is at Dehradun which has become congested. There is a move rather that is going on now, a proposal to build a new terminal there with a cost of ₹ 327.09 crores and the consultancy is being given right now. We expect it to be in place in November, 2018.

Sir, with regard to Pant Nagar, Air India, at present, has about four flights a week which they are thinking to make six weekly flights. They are in talk with the State Government on Viability Gap Funding. We hope that it will materialise. And if that materialises, the flights to Pant Nagar also will increase. The Government is interested in making our air vibrant and we are acting.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Second supplementary.

श्री तरुण विजयः माननीय सभापित महोदय, दुनिया का कोई हिन्दू नहीं होगा जो उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नहीं जाता होगा। वे उत्तराखंड आए बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आने से ही उन्हें पुण्य मिलता है। वहां पर गोचर एक ऐसी जगह है, जहां पर पहले से हवाई अड्डा बना हुआ है और आपने गोचर का नाम ही नहीं लिया। यात्रीगण गोचर के माध्यम से बद्रीनाथ और केदारनाथ आसानी से जा सकते हैं और इससे उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चूंकि पंतनगर में एयर ट्रेवल कभी भी कैंसिल हो जाता है, जिसके कारण हम पंतनगर के लिए हवाई टिकट की बुकिंग भी नहीं करवा पाते हैं, इसलिए क्या गोचर में हवाई सुविधा देने की आपकी कोई योजना है, जहां पर हवाई पट्टी पहले से ही बनी हुई है? अगर आप इसको बेहतर बना देंगे, तो यह पूरे उत्तराखंड से जुड़ जाएगा।

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU PUSAPATI: Sir, the air strip also belongs to the State Government. In fact, we are trying to bring out a policy which will make the non-operational airports operational. They are four and they are non-operational. They belong to the State Government. We are requesting the State Government to bring them into shape which will make the operations possible. We are working at it.

श्री महेन्द्र सिंह माहराः चेयरमैन सर, वर्ष 1960 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के समय से ही देश की सामरिक स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार ने तीन जिलों का निर्माण किया था, जो उत्तराखंड के नाम से जाने जाते थे। उन तीन जिलों के कारण ही "उत्तराखंड" नाम बना और वे जिले थे - उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने इन तीन हवाई पट्टियों के निर्माण हेतु कोई योगदान दिया है? यदि नहीं, तो क्या आप देश की रक्षा की दृष्टि से एवं 2013 की त्रासदी को ध्यान में रखते हुए इन हवाई पट्टियों के विस्तार हेतु धन उपलब्ध कराएँगे?

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU PUSAPATI: Sir, I have already mentioned that these four belong to the State Government and if they can be brought into an operational stage, then operations can start.

श्री नरेश अग्रवालः श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। केन्द्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों से यह प्रस्ताव माँगा था कि वे कौन-कौन से एयरपोर्ट्स अपग्रेड करना चाहती हैं या नये बनाना चाहती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश ने 16 प्रस्ताव भेजे थे।

श्री सभापतिः नरेश जी, सवाल दूसरा है। Let's stick to the question.

श्री नरेश अग्रवालः सर, यूपी और उत्तराखंड अलग-अलग नहीं हैं।

श्री सभापतिः वे बिल्कुल अलग हैं।

श्री नरेश अग्रवालः वह थोड़ा सा अलग पार्ट हो गया, लेकिन मैं उनके उत्तर ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः देखिए, don't commit aggression like this.

श्री नरेश अग्रवालः चेयरमैन साहब, मैं उत्तर से संदर्भित प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र है और राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्र को किन-किन राज्य सरकारों ने अपने राज्य में नये एयरपोर्ट्स स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं? अगर उनमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रस्ताव भेजे हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई है?

MR. CHAIRMAN: This is not related to the question.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU PUSAPATI: I can collect the information and reach it out to the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Fair enough. Shri C.M. Ramesh. ...(Interruptions)... That's all. ...(Interruptions)...

श्री महेन्द्र सिंह माहराः चेयरमैन सर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री सभापतिः अगर उत्तर नहीं मिला, तो आप मंत्री जी को लिखिए।

श्री महेन्द्र सिंह माहराः सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कह रहा हूं। ...(व्यवधान)...

SHRI C.M. RAMESH: Sir, recently, the hon. Minister opened an airport at Kadapa in Andhra Pradesh. That airport is not functioning because there are no flights. At that airport, only ATRs can land. Air India has some ATRs. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: One minute, please. ... (Interruptions)...

श्री महेन्द्र सिंह माहराः सर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Just sit down, अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, तो please point this out in a formal communication. ...(Interruptions)...

श्री महेन्द्र सिंह माहराः सर, यह तीन हवाई पट्टियों के बारे में है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: That's all right. ...(Interruptions)...

SHRI C.M. RAMESH: Sir, that airport has opened. That airport has to be expanded. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Where? ... (Interruptions)...

SHRI C.M. RAMESH: Kadapa Airport in Andhra Pradesh.

MR. CHAIRMAN: We are not discussing Andhra Pradesh. ...(Interruptions)...

SHRI C.M. RAMESH: Sir, he is the Minister for Civil Aviation. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No, no. I am sorry. ...(Interruptions)... Please don't create unnecessary confusion. This is a question in respect of Uttarakhand. ...(Interruptions)... Please read the question. ...(Interruptions)... Question No.107. Shri Bhupinder Singh. ...(Interruptions)...

श्री महेन्द्र सिंह माहराः सर, मेरा प्रश्न उत्तराखंड से ही संबंधित है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please complain if you have not got the answer. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)... You know the procedure. Now, please sit down. ...(Interruptions)... Question No.107.

श्री रामदास अठावलेः सर, मेरा भी एक प्रश्न है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप भी बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... I don't See a need for this indiscipline. ...(Interruptions)... आप बैठ जाइए, प्लीज़। ...(व्यवधान)... We are onto Question No.107.

Central assistance for Area Specific Development Programmes

*107. SHRI BHUPINDER SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether steps have been taken to continue Central assistance for the Area Specific Development Programmes like special plan for Kalahandi-Bolangir- Koraput region (KBK) in Odisha and Backward Region Grant Fund (BRGF) and Integrated Action Plan (IAP) in the country;
 - (b) if so, whether Government would continue to take steps; and
 - (c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): (a) to (c) Consequent to recommendation of 14th Finance Commission for increase in the States' share in divisible pool of Union taxes from 32% to 42%, Central Assistance to State Plans (CASP), including Backward Region Grant Fund and ACA for LWE affected districts (earlier known as Integrated Action Plan) has been subsumed in overall enhanced devolution to the States from Financial Year 2015-16. However, considering spillover liabilities of Backward regions, a provision of one time grant of